



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072022-237574  
CG-DL-E-26072022-237574

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]  
No. 184]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 26, 2022/श्रावण 4, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 26, 2022/SHRAVANA 4, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2022

(अंतिम जांच परिणाम)

मामला सं. सीवीडी-एसी - 01/2022

**विषय :** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सेकरिन” के आयातों पर लगाए गए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की, थाइलैंड से “सेकरिन” के आयातों के द्वारा कथित प्रवंचना की प्रवंचना-रोधी जांच में अंतिम जांच विवरण।

**फा. सं. 07/05/2022-डीजीटीआर.—**1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (रियायती वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995, जिसे इसके बाद “नियमावली” के रूप में भी कहा गया है, को ध्यान में रखते हुए;

2. जबकि, मैसर्स स्वाती पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद इसे “आवेदक” के रूप में कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे “प्राधिकारी” के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (रियायती वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान,

आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद “नियमावली” के रूप में कहा गया है) के अनुसार यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन दाखिल किया कि चीन (इसके बाद इसे “संबद्ध देश” के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सेकरिन” (इसके बाद इसे “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” या “संबद्ध वस्तुएं” भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए इन सब्सिडी-रोधी शुल्कों की थाइलैंड से निर्यातित “सेकरिन” (इसके बाद इसे “जांचाधीन उत्पाद” या “पीयूसी” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के माध्यम से प्रवंचना की जा रही है।

3. जबकि, आवेदक द्वारा नियम 26 (1) के तहत दाखिल किए गए विधिवत प्रमाण सहित एक आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने संगत पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, थाइलैंड से “सेकरिन” के आयातों पर लगाए गए सीवीडी की कथित प्रवंचना की मौजूदगी और प्रभाव का निर्धारण करने तथा मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का विस्तार करने की सिफारिश पर विचार करने के लिए दिनांक 17 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 07/05/2022- डीजीटीआर के तहत जांच शुरू की।

#### **क. मामले की पृष्ठभूमि**

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के माध्यम से और दिनांक 19 जून, 2019 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. सं. 6/18/2018- डीजीएडी (“मूल जांच”) के तहत पहले, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सेकरिन” के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. 01/2019- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत निश्चयात्मक सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाया गया था।

#### **वर्तमान प्रवंचना-रोधी जांच**

5. मैसर्स स्वाती पैट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद इसे “आवेदक” के रूप में कहा गया है) ने अधिनियम की धारा 9 (1) (i) और नियमावली के नियम 25 एवं 26 के अनुसार, थाइलैंड से उत्पादित और निर्यातित “सेकरिन” (इसके बाद इसे “जांचाधीन उत्पाद” अथवा (“पीयूआई”) भी कहा गया है) के आयातों के लिए चीन जन. गण. से “सेकरिन” के आयातों पर लगाए गए सब्सिडी-रोधी शुल्कों का विस्तार करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दाखिल किया है। आवेदक ने यह तर्क दिया है कि शुल्कों की प्रवंचना हो रही है, जैसा कि व्यापार की पद्धति में बदलाव से स्पष्ट है, जिससे कि लगाए गए शुल्कों के उपचारात्मक प्रभावों का असर कम हो रहा है और इसलिए लगाए गए सब्सिडी-रोधी शुल्क का विस्तार करने का अनुरोध किया है। तथ्यों की प्रथम दृष्टया जांच करने के बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 17 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 07/05/2022- डीजीटीआर के तहत यह प्रवंचनारोधी जांच शुरू की है।

#### **ख. प्रक्रिया**

6. संबद्ध जांच के संबंध में यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :-
  - i. प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार, प्रवंचना-रोधी याचिका शुरू करने के बारे में थाइलैंड और चीन जन. गण. के दूतावास को अधिसूचित किया।
  - ii. प्राधिकारी ने थाइलैंड (इसके बाद इसे प्रवंचनाकर्ता देश के रूप में भी कहा गया है) से जांचाधीन उत्पाद (इसके बाद इसे “पीयूआई” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में प्रवंचना-रोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 17 मार्च, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
  - iii. प्राधिकारी ने आवेदन में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में थाइलैंड और चीन जन. गण. के दूतावास, जांचाधीन उत्पाद के ज्ञात निर्यातकों, भारत में आयातकों को, जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति प्रेषित की।
  - iv. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद/ जांचाधीन उत्पाद के ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों को लिखा और उन्हें निर्धारित प्रश्नावली में अपने उत्तरों को दाखिल करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक

प्रति भी ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों की एक सूची के साथ थाइलैंड के दूतावास को भेजी गई, जिसमें निर्धारित समय के भीतर प्राधिकारी को उत्तर देने के लिए निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया।

- v. याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति थाइलैंड के उत्पादक/ निर्यातकों, थाइलैंड और चीन जन. गण. की सरकार और उनके उत्पादक/ निर्यातकों को भेजी गई। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति भी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर उन्हें सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।
- vi प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार थाइलैंड में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को संगत सूचना प्रकट करने के लिए प्रश्नावली भेजी :
  1. वारण्य केवपिकुल लिमिटेड
  2. तियानम कैमिकल इंडस्ट्रीज ट्रेड
  3. रॉयल कमोडिटी लिमिटेड
  4. सियाम सिटी कैमिकल कंपनी लिमिटेड
  5. बोरनेट कारपोरेशन कंपनी लिमिटेड
- vii. थाइलैंड से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया।
- viii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को भी पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-
  1. कॉलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड
  2. ईगल ट्रेडिंग कंपनी
  3. जनरल इम्पोर्ट कंपनी इंडिया
  4. स्पेशियलिटी केमिकल्स
  5. नंदलाल बकतलाल प्राइवेट लिमिटेड
  6. जगमोहनदास एंड संस सर्वोत्तम केयर लिमिटेड
  7. सी.जे. शाह एंड कंपनी
  8. नेक्टर ड्रग्स प्रा. लिमिटेड
  9. सन-शाइन कॉस्मेटिक्स लिमिटेड
- ix. जांच शुरू करने की अधिसूचना के उत्तर में उपरोक्त में से किसी भी आयातक, प्रयोक्ता और एसोसिएशन ने उत्तर नहीं दिया है अथवा प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। तथापि, चीन जन. गण. से, जांचाधीन उत्पाद के एक आयातक, नामतः मैसर्स इंदीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनुरोध किए हैं, जिन पर इस अंतिम जांच परिणाम में संगत स्थानों पर विचार किया गया है।
- x. निम्नलिखित कंपनियों, जो संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक हैं, ने जांचाधीन उत्पाद पर लगाए गए उपायों की प्रवंचना के खिलाफ आवेदन का समर्थन किया है :
  - क) श्री वरदायिनी कैमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
- xi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुली रखी एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को संगत पाए जाने के अनुसार इस अंतिम जांच परिणाम में शामिल किया गया है।

- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, उनके गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना के गोपनीय होने पर विचार किया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
- xiii. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यकता के अनुसार आगे सूचना की मांग की गई थी।
- xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था।
- xv. अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि (12 माह) (इसके बाद इसे “जांच की अवधि” अथवा “पीओआई” के रूप में कहा गया है) के लिए जांच की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल 2018 से मार्च 2019, अप्रैल 2019 से मार्च 2020, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल थी।
- xvi. डीजी सिस्टम्स को जांच की अवधि सहित विगत चार वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था और ये प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने तथा क्षति विश्लेषण करने के लिए डीजी सिस्टम्स के आयात डेटा का उपयोग किया है।
- xvii. सब्सिडी-रोधी नियमावली के नियम 18 के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 23 मई, 2022 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान किया। सभी पक्षकारों से दिनांक 30 मई, 2021 तक अपने लिखित अनुरोध दाखिल करने का अनुरोध किया गया था। चूंकि कोई विरोध नहीं था, अतः कोई रिज्वाइंडर अनुरोध बकाया नहीं था।
- xviii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान करने से इंकार किया है अथवा अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच को छिपाया है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणियां दर्ज की हैं।
- xix. इस अंतिम जांच परिणाम में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत इस पर विचार किया है।
- xx. यूएस डॉलर को भारतीय रुपए में परिवर्तित करने के लिए जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 75.14 रुपए मानी गई है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद/ जांचाधीन उत्पाद और समान वस्तु

#### विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई)

#### ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- i. विगत जांचों और वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद “इसके सभी रूपों में सेकरिन” है।
- ii. सेकरिन को उप शीर्ष सं. 29251100 के अन्तर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अन्तर नहीं है। वे तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अन्तिम उपयोगों के संदर्भ में तुलनीय हैं। वे तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। अतः इन्हें नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं माना जाना चाहिए।

## ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. किसी भी निर्यातक, आयात, उपभोक्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दाखिल नहीं किया है।

## ग.5 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सैकरिन" के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की एक प्रवंचना-रोधी जांच है। अतः वर्तमान जांच में विचाराधीन का दायरा मूल प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/ सस्सिडी-रोधी जांच अर्थात् दिनांक 19.06.2019 के अन्तिम जांच परिणामों में परिभाषित किए अनुसार वही रहा, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है :

*"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद अपने सभी रूपों में "सैकरिन" है। "सैकरिन" एक गैर-न्यूट्रिटिव स्वीटनर है और उसे गन्ने की चीनी का कम कैलोरी वाला प्रतिस्थापक माना जाता है। प्राथमिक रूप से दो प्रकार के सैकरिन होते हैं अर्थात् विलेय और अविलेय। बाजार शब्दावली में विलेय सैकरिन को सोडियम सैकरिन कहा जाता है जबकि अविलेय सैकरिन को सैकरीन या सैकरीन एसिड कहा जाता है। सैकरीन को दो भौतिक रूपों में उत्पादित किया जाता है अर्थात् दानेदार और पाउडर। सोडियम सैकरीन को दानेदार रूप में उन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है जहां सैकरीन घुल जाती है, पाउडर रूप जिसे पीसा और स्प्रे ड्राई किया जाता है को शुष्क मिश्रणों और भेषजों में प्रयोग किया जाता है। यह जल में थोड़ा विलेय होता है। सैकरिन का अविलेय रूप अनेक भेषजों और चिकित्सीय अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। सैकरिन को अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबल टॉप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, भेषज आदि। सैकरीन के सभी रूप वर्तमान जांच के दायरे के भीतर आते हैं।"*

10. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सैकरिन" है। जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई) थाइलैंड से निर्यातित "सैकरिन" है, जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष सं. 29251100 के अन्तर्गत वर्गीकृत "जांचाधीन उत्पाद" अथवा "पीयूआई" के रूप में भी उल्लिखित किया गया है।
11. प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु थाइलैंड से आयातित वस्तु के "समान वस्तु" है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और थाइलैंड से आयातित वस्तुएं तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों, अथवा अन्तिम उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।
12. तथापि, विचाराधीन उत्पाद का उपरोक्त वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

## घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

### घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-
- मैसर्स स्वाती पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रवंचना-रोधी जांच के लिए आवेदन दाखिल किया है। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन भारत में चार उत्पादकों द्वारा किया जाता है। आवेदन के लिए मैसर्स ए.एस. केमोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स श्री वरदायिनी कैमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड द्वारा समर्थन किया गया है।
  - आवेदक आधारीक जरूरत को पूरा करता है और यह पाटनरोधी नियमावली के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

### घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता तथा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दाखिल नहीं किया है।

**घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

15. यह आवेदन मैसर्स स्वाती पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदन के लिए मैसर्स ए.एस. केमोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स श्री वरदायिनी कैमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड द्वारा समर्थन किया गया है। मैसर्स श्री वरदायिनी कैमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने भी क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों पर सूचना दाखिल की है।
16. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 30 प्रतिशत है। इस प्रकार आवेदक, नियम 2(घ) के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग है।

**ड. प्रवंचना का साक्ष्य****च.1 घरेलू उद्योग के विचार**

17. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :-

- i. थाइलैंड से निर्यात थाइलैंड में उत्पादित “सेकरिन” के नहीं हैं। इसकी बजाय, ये उत्पाद चीन के मूल के हैं, जो केवल प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के भुगतान से बचने के लिए थाइलैंड के माध्यम से निर्यात किए जा रहे हैं।
- ii. संबद्ध वस्तुएं पहले चीन जन. गण. से भारत को सीधे भेजी जाती थी। तथापि, चीन जन. गण. से सेकरिन के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के कारण आयातों की मात्रा चीन जन. गण. से कम की गई है तथा थाइलैंड से काफी मात्रा में आयात शुरू किए गए।
- iii. चीन से थाइलैंड को निर्यातों में जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है, इस प्रकार से उस देश की, निर्माण की बजाय आयातों पर निर्भरता को दर्शाता है। चूंकि इंडोनेशिया से आयातों में भी पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद गिरावट आई है, अतः इंडोनेशिया से थाइलैंड को आयातों की भी जांच की गई थी। इंडोनेशिया से थाइलैंड को सेकरिन के कोई निर्यात नहीं थे। ये तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि चीन की वस्तुएं थाइलैंड के माध्यम से प्रवंचना करके भेजी जा रही हैं।
- iv. किसी भी निर्यातक ने जांच का उत्तर नहीं दिया है और इस प्रकार थाइलैंड में वास्तविक उत्पादन की कोई भी सूचना या दावा नहीं है।
- v. चीन जन. गण. से भारत में आयातों की मात्रा में, विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के कारण गिरावट आई है।
- vi. शुल्कों को लगाए जाने के बाद, चीन जन. गण. से आयातों और इंडोनेशिया से आयातों में काफी गिरावट आई है। तथापि, चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से आयातों द्वारा खाली हुआ बाजार हिस्सा थाइलैंड के माध्यम से चीन के निर्यातकों से आयातों द्वारा ले लिया गया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग, बाजार के उचित वैध हिस्से से वंचित हो गया है।
- vii. घरेलू बाजार का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा थाइलैंड के पास है। चीन के मूल की वस्तुओं का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में 31 प्रतिशत पहुंच गया है (थाइलैंड से प्रवंचना आयातों के साथ) और भारतीय उद्योग का समग्र बाजार हिस्सा जांच की अवधि में 62 प्रतिशत तक कम हो गया है।
- viii. थाइलैंड से आयातों की पहुंच कीमत भारत में बिक्री कीमत से काफी कम है, अतः इनसे घरेलू बाजार में कीमतों में काफी कटौती हो रही है। विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में कीमत कटौती में काफी वृद्धि हुई है।
- ix. चीन की प्रवंचना के कारण (क) मांग में भारतीय बाजार के हिस्से में कमी; (ख) काफी हद तक कीमत कटौती और शुल्कों में कटौती हुई है।
- x. थाइलैंड से आए काफी आयात पूरा सीमा शुल्क भुगतान किए जाने के बाद सीमा शुल्क द्वारा अनुमत कर दिए गए थे। एशियाई - भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए) के तहत विचाराधीन उत्पाद को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्या एक सही उत्पादक को पूरे सीमा शुल्कों के साथ आयात के लिए उत्पाद का निर्यात करना चाहिए, जबकि वे आसानी से एआईएफटीए के तहत रियायत का लाभ ले सकते हैं।

- xi. यूरोपीय आयोग ने अनेक निर्णयों में, केवल आयात के आंकड़ों के आधार पर, व्यापार पैटर्न में बदलाव तथा उपचारी प्रभाव को कम करने के आधार पर प्रवंचना को समाप्त किया है। संबंधित देश में उत्पादक सुविध मौजूदा होना भी निर्धारण के लिए कोई प्रश्न नहीं है।

## च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :

- थाइलैंड और कम्बोडिया से आयातों में क्षेत्रीय सामग्री के मूल्य की जांच की जानी चाहिए। यह कम से कम 35 प्रतिशत होनी चाहिए। कारोटर घोषणा की जांच की जानी चाहिए। एशियाई - भारत मुक्त व्यापार करार (एआईएफटीए) मूलता के प्रमाण-पत्र की जांच की जानी चाहिए।
- थाइलैंड और कम्बोडिया से आयात प्राथमिक रूप से संदिग्ध दिखाई देते हैं। शुल्क की प्रवंचना/ मिथ्या घोषणा की पूरी संभावना है, जिसका पता लगाया जाना आवश्यक है। निर्यातक अलग देश से है। वित्तीय सौदों की जांच करने की जरूरत है।
- निर्यातकों और आयातकों से दस्तावेजों की जांच शामिल है। घरेलू उद्योग के अगोपनीय पाठ में उनके नाम उल्लिखित नहीं हैं।
- थाइलैंड और कम्बोडिया से आयातों पर बुनियादी शुल्क और बुनियादी शुल्क पर कोई उप कर नहीं है तथा बुनियादी शुल्क पर कोई जीएसटी अथवा उप कर पर कोई जीएसटी नहीं है।
- निर्यातक का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।
- थाइलैंड और कम्बोडिया किसी भी देश से खरीद कर सकते हैं। अतः चीन को अलग नहीं किया जाना चाहिए।
- चीन से पहुंच लागत काफी अधिक है।
- थाइलैंड और कम्बोडिया के पाटन के कारण स्थानीय कीमतों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि चीन प्रतिस्पर्धी नहीं है।

## च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और अधिनियम/ नियम के संगत प्रावधान इस प्रकार हैं :-

### सीवीडी नियमावली का नियम 25 :

पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना – (1) प्रवंचना पर किसी परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य, जिसके लिए शुल्क लगाए जाने को छोड़कर अपर्याप्त कारण अथवा आर्थिक औचित्य है, के परिणामस्वरूप भारत और उपायों के अध्यक्षीन किसी देश में अलग-अलग कंपनियों के बीच अथवा किसी देश और भारत के बीच व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के रूप में विचार किया जाएगा; और जहां क्षति का साक्ष्य है अथवा शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव कीमतों अथवा गुणवत्ताओं अथवा समान उत्पाद के दोनों के संदर्भ में कम किए जा रहे हैं, और जहां समान उत्पाद के लिए पूर्व में सिद्ध सामान्य मूल्यों के संबंध में पाटन का साक्ष्य है, यदि उपयुक्त परिवर्तनों अथवा समायोजनों अथवा नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक हो।"

- (2) उप नियम (1) में उल्लिखित परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन किसी वस्तु का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित निर्यातक देश अथवा मूल देश सहित किसी भी देश से भारत में अनअसेंबल, अनफिनिशड अथवा इनकम्प्लीट रूप में किया जाता है तथा उसे भारत में अथवा ऐसे देश में असेंबल, फिनिशड अथवा कम्प्लीट किया जाता है तो ऐसी असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन को लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना माना जाएगा, यदि:

(i) प्रचालन पाटनरोधी जांच के बाद अथवा ठीक उससे पूर्व प्रारंभ किया गया हो अथवा बढ़ाया गया हो तथा हिस्से पुर्जों एवं संघटकों का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित मूल देश अथवा निर्यातक देश से आयात किया गया हो; और

(ii) असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन के कार्य के परिणामस्वरूप मूल्य असेंबलड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत के 35 प्रतिशत से कम हो।

व्याख्या-I – मूल्य का अर्थ असेंबलड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत में से आयातित हिस्सों पुर्जों अथवा संघटकों का मूल्य घटाकर।

व्याख्या-II – “मूल्य” का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा परामर्शी प्रभारों से संबंधित भुगतानों के निमित्त किए गए खर्चों को हिसाब में नहीं दिया जाएगा।

(ख) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन कोई वस्तु मूल देश से अथवा वस्तु के विवरण, नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन में शामिल किसी प्रक्रिया के अध्यक्षीन रखे जाने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यात के देश से भारत में आयात किए जाते हैं, वहां ऐसे परिवर्तन लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन उस वस्तु के विवरण अथवा नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन के फलस्वरूप प्रशुल्क वर्गीकरण, यदि कोई है, के अंतर को ध्यान में रखते हुए छोटे रूपों में भी दिखाई देने वाले अथवा उस स्वरूप में वस्तु में परिवर्तन हो रहा है।

(ग) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन कोई वस्तु उस निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा देश के माध्यम से भारत में आयातित की जाती है जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है तो ऐसे निर्यात लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यातक अथवा उत्पादक उस वस्तु की अपनी व्यापार परिपाटी, व्यापार पैटर्न अथवा बिक्री के चैनल में निर्यातकों अथवा उत्पादकों अथवा उस देश के माध्यम से भारत में निर्यातित अपने उत्पादों को देने के लिए परिवर्तन करते हैं जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं हैं।

(घ) अन्य कोई तरीका जिससे इस प्रकार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी किया गया है।

20. विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद, दोनों के आयातों की जांच के प्रयोजन के लिए, याचिकाकर्ता ने डीजीसीआई एंड एस द्वारा उपलब्ध न कराए जाने को देखते हुए, व्यापार मानचित्र से सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त किए। तथापि, प्राधिकारी ने भारत में जांचाधीन उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद के आयातों का विश्लेषण करने के लिए डीजी सिस्टम्स द्वारा प्रदान किए गए सौदा-वार आंकड़ों पर विचार किया है। थाइलैंड द्वारा तीसरे देशों को निर्यात और अन्य देशों द्वारा थाइलैंड में आयात के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए व्यापार मानचित्र के डेटा पर विचार किया गया है।
21. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीवीडी उपाय उत्पादक/ निर्यातक से संबंधित हैं। उत्पादकों/ निर्यातकों की सीवीडी जांच में संगत आंकड़े/ सूचना प्रदान करने होते हैं ताकि प्राधिकारी कोई निर्धारण कर सके। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांचाधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने कोई सूचना प्रदान नहीं की है।

### च.3.1 व्यापार की पद्धति में बदलाव

22. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद से जांचाधीन उत्पाद में व्यापार पद्धति में बदलाव पर निर्दिष्ट मानदंड की जांच की है अर्थात् क्या व्यापार पद्धति में बदलाव किसी आर्थिक औचित्य से आया है या नियम 25 (1) के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद पर सीवीडी लगाए जाने के कारण से आया है।
23. व्यापार की पद्धति में बदलाव के लिए, विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर मात्रा का विश्लेषण करते हुए वर्ष 2018-19 से जांच की अवधि तक का विश्लेषण किया गया है।

वर्ष	जांचाधीन उत्पाद के आयात (मी. टन)	विचाराधीन उत्पाद के आयात (मी. टन)
2018-19	-	712
2019-20	-	776
2020-21	23	776
2021-22	176	455



## स्रोत : डीजी सिस्टम्स

24. यह देखा गया है कि थाइलैंड से आयात 2018-19 तक अन्यथा मौजूद नहीं थे, इनका प्रवेश घरेलू बाजार में वर्ष 2020-21 में पहली बार हुआ था। तदनुसार, दिनांक 30 अगस्त, 2019 को चीन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद से चीन से आयातों की मात्रा में गिरावट शुरू हो गई।
25. प्राधिकारी ने विभिन्न देशों से थाइलैंड को वैश्विक रूप से सेकरिन के आयातों तथा थाइलैंड से अन्य देशों को सेकरिन के निर्यातों की भी जांच की है।

विवरण	2017	2018	2019	2020	2021
थाइलैंड में आयात (मी. टन)	1,054	1,008	1,044	1,432	1,584
आयात कीमत (यूएस डॉलर/ कि.ग्रा.)	7.45	7.95	11.55	7.18	7.13
थाइलैंड से निर्यात (मी. टन)	0.36	0.78	6.80	157	1,185
निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ कि.ग्रा.)	25.21	23.23	1.76	5.75	6.44

## स्रोत : व्यापार मानचित्र

- 26 यह पाया गया है कि :
- क. थाइलैंड ऐतिहासिक रूप से सेकरिन का आयात कर रहा है। इन आयातों में वर्ष 2019 में 1044 मी. टन से वर्ष 2020 में 1432 मी. टन और वर्ष 2021 में 1584 मी. टन तक वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2019 तक थाइलैंड से शून्य या कम निर्यात थे।
- ख. थाइलैंड में अधिकांश आयात (वर्ष 2017 से 2021 तक की अवधि के दौरान करीब 95 प्रतिशत) चीन से हैं, जबकि कुछ मात्रा में आयात अन्य देशों जैसे भारत, जापान और साउथ कोरिया से भी किए गए हैं।
- ग. थाइलैंड से भारत को और अन्य देशों को निर्यात कीमत थाइलैंड में आयात कीमत से कम हैं।
27. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि थाइलैंड से निर्यातकों ने सहयोग नहीं करने को तरजीह दी है और भारत को निर्यातित सामग्री की मूलता के संबंध में कोई भी सूचना प्रदान नहीं की है, जो यह दर्शाता है कि थाइलैंड में कोई वास्तविक उत्पादक नहीं है।
28. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य प्रदान किए हैं कि थाइलैंड में, निर्यातक चीन में उत्पादित जांचाधीन उत्पाद को भेज रहे हैं। चूंकि किसी अन्य पक्षकार द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है, जो थाइलैंड में उत्पाद के घरेलू उत्पादन को दर्शा सके और न ही किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने सहयोग किया है, अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि थाइलैंड से निर्यातित वस्तुएं चीन के मूल की हैं, जिसने उस उत्पाद में चीन जन. गण. द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी को शामिल किया गया है, जो पहले ही मूल जांच में तय किया जा चुका है।

**च.3.2 सब्सिडी-रोधी शुल्क लगाने के अलावा आर्थिक अथवा अन्यथा औचित्यकरण**

29. यह नोट किया जाता है कि थाइलैंड से आयातों से एशियाई – भारत मुक्त व्यापार करार (एआईएफटीए) के तहत रियायती सीमा शुल्क लगाया गया है। सेकरिन के आयात पर वर्तमान बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत है जबकि थाइलैंड से सेकरिन के आयात के लिए अधिमान्य टैरिफ एआईएफटीए के अंतर्गत 0 प्रतिशत है। डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़ों के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान और जांच की अवधि के दौरान थाइलैंड से सभी आयात पूरा सीमा शुल्क भुगतान करने के बाद किए गए हैं, जबकि चीन जन.गण. से सभी आयात इसी अवधि के दौरान सीमा शुल्क का और यथा लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का भुगतान करने के बाद किए गए हैं।
30. यह भी नोट किया जाता है कि जबकि आवेदक ने यह दावा किया है कि थाइलैंड में सेकरिन का कोई उत्पादक नहीं है, सौदा-वार आयात के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि थाइलैंड से भारत में आयात थाइलैंड मूल के हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि थाइलैंड से आयातित जांचाधीन उत्पाद वास्तव में चीन के मूल के हैं।

31. इसके अलावा, थाइलैंड से उत्पादक/ निर्यातक से किसी सहयोग के अभाव में, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्यातकों ने मूलता के देश में बदलाव के लिए कुछ अपर्याप्त क्रियाकलाप किए हैं, लेकिन ये किसी भी एआईएफटीए के तहत रियायतों का लाभ पाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, न ही ये यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि निर्यातों में शुल्क की प्रवंचना शामिल नहीं है।
32. अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि थाइलैंड से आयात वास्तव में चीन के मूल के हैं और चीन जन. गण. के मूल की या वहां से निर्यातित सेकरिन के आयात पर लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के भुगतान से बचने के अलावा, जांचाधीन उत्पाद से विचाराधीन उत्पाद को भेजने के लिए कोई अन्य उचित कारण या आर्थिक औचित्य नहीं है।

### च.3.3 मौजूदा सब्सिडी-रोधी उपायों और घरेलू उद्योग पर प्रवंचना के प्रभाव का आकलन

33. किसी प्रवंचना रोधी जांच में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहले लगाए गए सब्सिडी रोधी शुल्क के उपचारी प्रभाव कम हो रहे हैं, अतः प्राधिकारी ने ऐसे तरीके, जिसमें और प्रवंचना के उत्पादों से लगाए गए शुल्क में कमी करने की जांच की और उससे ऐसे शुल्क को अनावश्यक किया गया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या सब्सिडी-रोधी शुल्कों के उपचारी प्रभाव बाजार अंश के संदर्भ में कम हुए हैं और थाइलैंड से जांचाधीन उत्पाद के आयातों के कारण कीमत कम हो रही है।

#### च.3.3.1 बाजार अंश का आकलन

34. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांचाधीन उत्पाद के आयातों के बाजार अंश की जांच की है, जो इस प्रकार है :-

मांग में बाजार अंश	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
भारतीय उद्योग की बिक्रियां	%	42	50	55	62
संबद्ध देश – थाइलैंड	%	0	0	1	10
सीवीडी वाला देश – चीन	%	36	45	39	21
अन्य देश	%	22	5	5	7
कुल मांग अंश	%	100	100	100	100

35. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 तक घरेलू बाजार में थाइलैंड से कोई आयात नहीं थे। तथापि, चीन जन. गण. पर शुल्क लगाए जाने के साथ ही, थाइलैंड ने वर्ष 2020-21 में एक प्रतिशत बाजार पर कब्जा कर लिया और इसके हिस्से में वृद्धि जांच की अवधि में 10 प्रतिशत तक हो गई। चीन जन. गण. का बाजार अंश वर्ष 2019-20 में 39 प्रतिशत से घटकर जांच की अवधि में 21 प्रतिशत तक आ गया। घरेलू उद्योग चीन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को लगाए जाने के बाद कुछ बाजार अंश बढ़ाने में समर्थ हुआ था। तथापि, वह थाइलैंड के माध्यम से प्रवंचना वाले, चीन के रियायती निर्यातों के कारण अपना उचित बाजार अंश आगे नहीं बढ़ा पाया।

### च.3.4 जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद की निवल बिक्री वसूली पर प्रवंचना के प्रभाव

36. कीमतों पर जांचाधीन उत्पाद के आयातों के प्रभावों के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में प्रवंचना के आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है। प्राधिकारी ने इस पर निम्नलिखित अनुसार विचार किया है :-

कीमत कटौती	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
थाइलैंड से आयातों की पहुंच कीमत	रु./ कि.ग्रा.	-	-	474	532
निवल बिक्री वसूली	रु./ कि.ग्रा.	-	-	***	***
निवल बिक्री वसूली	प्रवृत्ति			100	103
कीमत कटौती	रु./ कि.ग्रा.	-	-	***	***

कीमत कटौती	प्रवृत्ति			100	71
कीमत कटौती	%	-	-	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	-	-	20-30	10-20

37. यह देखा गया है कि थाइलैंड से आयातों की पहुंच कीमत, जब से इसने वर्ष 2018-19 में घरेलू बाजार में प्रवेश करना शुरू किया है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।

38. प्राधिकारी ने नीचे दी गई तालिका में चीन से कीमत कटौती के स्तर की जांच की है :

कीमत कटौती	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
चीन जन. गण. से आयातों की पहुंच कीमत	रु./ कि.ग्रा.	450	473	668	602
सीवीडी के साथ पहुंच कीमत	रु./ कि.ग्रा.	450	473	791	713
निवल बिक्री वसूली	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
निवल बिक्री वसूली	प्रवृत्ति	100	112	121	126
कीमत कटौती (बिना सीवीडी)	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती (बिना सीवीडी)	प्रवृत्ति	100	176	-143	46
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	0-10	10-20	नकारात्मक	0-10
सीवीडी के साथ कीमत कटौती	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
सीवीडी के साथ कीमत कटौती	प्रवृत्ति	100	176	-411	-196
सीवीडी के साथ कीमत कटौती	%	***	***	***	***
सीवीडी के साथ कीमत कटौती	% रेंज	0-10	10-20	नकारात्मक	नकारात्मक

39. सब्सिडी-रोधी शुल्क अगस्त, 2019 में लगाए गए थे। अतः शुल्क जांच की अवधि में प्रभावी थे। यह देखा गया है कि चीन जन. गण. से (सीवीडी के साथ) विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर कीमत कटौती जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक थी।

### च.3.5 प्रतिसंतुलनकारी लाभ थाइलैंड से निर्यात की गई वस्तुओं पर लागू है

40. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की जांच से यह साबित होता है कि थाइलैंड के माध्यम से निर्यात किए जा रहे सामान चीन जन. गण. के मूल के हैं। इस तथ्य के संबंध में कि थाइलैंड से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने यह साबित करने के लिए जांच में भाग नहीं लिया है कि भारत में आयातित जांचाधीन उत्पाद थाइलैंड में उत्पादित किए गए थे, अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि भारत में आयातित जांचाधीन उत्पाद चीन के मूल के हैं और इस प्रकार उन सब्सिडियों से लाभान्वित हुए हैं, जो पहले चीन के निर्माताओं को लाभान्वित करने में पाई गई थी। यह विशेष रूप से तब है जब सब्सिडी की प्रकृति से पहले भी निर्यातों को लाभ हुआ है, जो या तो उत्पादन से या निर्यात से संबद्ध थी, और ये केवल भारत के लिए सीधे निर्यातों के लिए सीमित नहीं थी।

### च.3.6 जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के प्रभाव में कमी

41. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की मात्रा निर्धारित की है, जो थाइलैंड से जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर भुगतान की जानी थी। नीचे दी गई तालिका में विचाराधीन उत्पाद पर सब्सिडी-रोधी उपायों की कमी की राशि निर्धारित की गई है :

अवधि	थाइलैंड से आयातों की मात्रा	सीआईएफ कीमत	विचाराधीन उत्पाद पर सब्सिडी-रोधी शुल्क - चीन	सब्सिडी-रोधी शुल्क	प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की कमी की मात्रा
	मी. टन	रु./ कि.ग्रा.	%	रु./ कि.ग्रा.	लाख रु.
2018-19	-		20		
2019-20	0		20		
2020-21	23	474	20	94.6	22
2021-22	176	532	20	106.4	187
<b>कुल</b>					<b>209</b>

42. यह देखा गया है कि इन आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में 209 लाख रु. की राशि का भुगतान किया जाना था, यदि इन्हें चीन के मूल का घोषित किया जाता।

#### ख. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

##### ख.1 घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियां

43. घरेलू उद्योग प्राधिकारी की टिप्पणियों से सहमत हो गया है। यह दोहराया जाता है कि:

- चीन से भारत में आयातों की मात्रा में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के समय से गिरावट आई है। तदनुसार, उसी अवधि के दौरान थाइलैंड से आयात शुरु हुआ और अब वह और अधिक हो गया है। इस प्रकार व्यापार के पैटर्न में स्पष्ट परिवर्तन है।
- थाइलैंड से पूर्व में कोई आयात नहीं हुआ है और ऐसा कोई ज्ञात उत्पादक नहीं है जो निर्माण में शामिल है, व्यापार के पैटर्न में उपर्युक्त परिवर्तन के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के अलावा कोई अन्य औचित्य, आर्थिक अन्यथा नहीं हो सकता है क्योंकि थाइलैंड से आयात की कीमत बिना प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जोड़े हुए भी चीन से आयात के कीमत के स्तर से बहुत कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र उद्देश्य लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क से प्रवंचना करना है।
- थाइलैंड से भेजे गए आयातों की पहुंच कीमत भारत में बिक्री कीमत से बहुत अधिक कम है और इस प्रकार उसके कारण घरेलू बाजार में कीमतों में कटौती हो रही है।
- थाइलैंड के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग चीन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद कुछ बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम रहा था, हालांकि इसे थाइलैंड के माध्यम से प्रवंचना की जा रही चीन के सब्सिडीयुक्त निर्यातों के कारण अपने औचित्यपूर्ण बाजार हिस्से में आगे वृद्धि करने से रोका गया है।
- प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि थाइलैंड से 2020-21 के दौरान और जांच की अवधि के दौरान किए गए सभी आयात पूर्ण रूप से सीमा शुल्क के भुगतान के बाद किए गए हैं। इस प्रकार, एफटीए के अन्तर्गत रियायती शुल्क होने के बावजूद, निर्यातक शुल्क से दी गई छूट का उपयोग करने में सक्षम नहीं रहे हैं क्योंकि निर्यातक एफटीए के अंतर्गत मूल आवश्यकताओं के नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं रहे हैं। इससे यह तर्क मजबूत हो जाता है कि ये वस्तु चीन के मूल के हैं।
- भारत में आयात किया गया जांचाधीन उत्पाद चीन के मूल का है और इस प्रकार इसने कुल सब्सिडी को लाभ पहुंचाया है, जिन्हें पहले चीन के निर्माताओं को लाभ पहुंचाता हुआ पाया गया था। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि ये लाभ जो चीन में उत्पादकों को उपलब्ध थे, अब मौजूद नहीं हैं।

##### ख.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के बाद कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृतिक प्रवृत्ति के हैं। इन अनुरोधों की जांच पहले ही इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर की गई है।

**ज. निष्कर्ष**

46. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच के अधीन उत्पाद के मामले में व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। यह देखा गया है कि थाइलैंड से आयात जो अन्य प्रकार से 2018-19 तक अस्तित्व में नहीं थे, ने पहली बार 2020-21 में घरेलू बाजार में प्रवेश करना शुरू किया। उसी अवधि के दौरान, 30 अगस्त, 2019 को चीन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के बाद, चीन से आयातों की मात्रा में गिरावट आनी शुरू हो गई।
  - थाइलैंड से निर्यात की गई वस्तु चीन के मूल की है जिसमें इस उत्पाद में चीन जन.गण. द्वारा दी गई सब्सिडी को शामिल किया, जिसकी मात्रा पहले ही इस मूल जांच में बताई जा चुकी है।
  - चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए सैकरीन के आयात पर लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के भुगतान से बचने के अलावा जांच के अधीन उत्पाद से विचाराधीन उत्पाद को जहाज द्वारा भेजे जाने के लिए कोई अन्य उचित कारण अथवा आर्थिक औचित्य नहीं है।
  - जांच के अधीन उत्पाद के आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं।
  - जांच के अधीन उत्पाद के आयात के कारण दिनांक 30 अगस्त, 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 02/2019-सीमा शुल्क(सीवीडी) के माध्यम से लगाया गया विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा सीवीडी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को नुकसान पहुंचाया है।
  - विचाराधीन उत्पाद पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के समाप्त होने के कारण वाणिज्यिक लाभ से जांच के अधीन उत्पाद का निर्यात कर उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ हुआ है।
  - प्राधिकारी को एक आयातक, मै. संदीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से जांच के संबंध में टिप्पणियां भी प्राप्त हुई हैं। उक्त आयातक ने यह उल्लेख किया है कि थाइलैंड और कम्बोडिया से आयात प्राथमिक रूप से संदेहास्पद लगते हैं और शुल्क से बचने/गलत घोषणा करने की प्रबल संभावनाएं हैं जिनके संबंध में यह सुनिश्चित किया जाना है कि निर्यातक एक अलग देश से हैं। प्राधिकारी ने आयातक के तर्कों को नोट करते हुए प्रवंचना की घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करते समय, उस पर विचार किया है।

**झ. सिफारिशें**

47. प्राधिकरण उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, थाइलैंड में उत्पन्न या निर्यातित सैकरीन के आयात पर 30 अगस्त, 2019 की कस्टम अधिसूचना संख्या 02/2019- सीमा शुल्क (सीवीडी) के तहत लगाए गए चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यातित वस्तुओं के विषय पर मौजूदा काउंटरवेलिंग शुल्क के विस्तार की सिफारिश करता है।
48. जांच के अधीन उत्पाद पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की वैधता दिनांक 30 अगस्त, 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 02/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी) के माध्यम से चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद अर्थात् "सैकरीन" पर शुल्क की अवधि के साथ होगा।

**ञ. आगे की प्रक्रिया**

49. इस जांच परिणाम के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2022

**(Final Findings)****Case No. CVD-AC - 01/2022**

**Subject : Final Finding statement in Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention of countervailing/anti-subsidy duty imposed on imports of “Saccharin” originating in or exported from China PR, by imports of “Saccharin” from Thailand.**

**F. No. 07/05/2022-DGTR.**—1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, hereinafter also referred as the "Rules", thereof;

2. Whereas, M/s Swati Petro Products Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant” filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “ Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as “Rules”) alleging that these anti-subsidy duties imposed on imports of “Saccharin” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “PUC” or the “subject goods”), originating in or exported from China (hereinafter also referred to as the “subject country”) are being circumvented by way of, imports of “Sachharin” exported from Thailand [hereinafter also referred to as “Product Under Investigation” or the “PUI”].
3. Whereas, in view of a duly substantiated application filed by the applicant under Rules 26 (1), the Authority initiated the investigation vide Notification No. 07/05/2022-DGTR dated 17<sup>th</sup> March, 2022 to determine the existence and effect of the alleged circumvention of the CVD levied and to consider recommendation of extension of exiting countervailing duty on imports of “Saccharin” from Thailand, in accordance with the relevant AD Rules.

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

4. The Designated Authority, through countervailing duty investigation and vide final finding Notification F.No. 6/18/2018-DGAD dated 19<sup>th</sup> June, 2019, (“original investigation”) had earlier recommended imposition of anti-subsidy duty on imports of “Saccharin” originating in or exported from China PR, and the definitive anti-subsidy duty was imposed by the Ministry of Finance, vide Notification No. 01/2019-Customs (ADD) dated 30<sup>th</sup> August, 2019.

**Present anti-circumvention investigation**

5. M/s Swati Petro Products Private Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application requesting extension of the anti-subsidy duties imposed on the imports of “Saccharin” from China PR to the imports of “Saccharin” produced and exported from Thailand [hereinafter also referred to as the “Product Under Investigation” or the (“PUI”), in accordance with with Section 9(1)(i) of the Act and Rules 25 & 26 of the CVD Rules. The applicant contended that there is circumvention of duties, as evident from the change in pattern of trade which is undermining the remedial effects of duties imposed and requested for extension of the anti-subsidy duty imposed. After *prima facie* examination of facts, the Designated Authority initiated this anti-circumvention investigation vide Notification No. 07/05/2022-DGTR dated 17<sup>th</sup> March, 2022.

**B. PROCEDURE**

6. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation.
  - i. The Authority notified the Embassy of Thailand and China PR about the initiation of anti-circumvention petition in accordance with the Act and the Rules.

- ii. The Authority issued a public notice dated 17<sup>th</sup> March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-circumvention investigation concerning imports of product under investigation (hereinafter also referred to "PUI" from Thailand (hereinafter also referred to as the circumventing country).
- iii. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the Embassy of Thailand and China PR in India, known exporters of the PUI, importers in India as per the information available in the application.
- iv. The Authority wrote to the known exporters/ producers of the PUC/PUI and requested them to file their responses in the prescribed questionnaire and make their views known in writing within the time limit prescribed. A copy of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Embassy of Thailand along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/ producers to respond to the Authority within the prescribed time.
- v. A copy of the non-confidential version of the application filed by the petitioner was sent to the producer/exporters of Thailand producer/ exporters, and the Government of Thailand and China PR. A copy of the non-confidential version of the application was also made available to the interested parties, on request, through public file.
- vi. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in Thailand in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
  1. Waranya Kaewpikul Ltd.
  2. Tiannam Chemical industrial trade
  3. Royal Commodity Ltd
  4. Siam City Chemical Co.,Ltd
  5. Bornet Corporation Company Ltd.
- vii. None of the producer exporter from Thailand filed exporter questionnaire response.
- viii. Questionnaires were also sent to the following known importers, users and associations of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
  1. Colgate Palmolive India Ltd
  2. Eagle Trading Company
  3. General Import Co. India
  4. Speciality Chemicals
  5. Nandlal Bakatlal Pvt Ltd
  6. Jagmohandas & Sons Sarvotham Care Ltd.
  7. C.J. Shah & Co
  8. Nectar Drugs P Ltd.
  9. Sun-Shine Cosmetics Ltd.
- ix. In response to the initiation notification, none of the above-mentioned importers, users and associations have responded or filed the questionnaire response. However, one of the importer of the PUI from China PR, namely, M/s Sandeep Organics Private Limited has made submissions which have been considered at relevant places in this final finding.
- x. Following companies who are producers of the subject goods have supported the application against circumvention of measures imposed on the PUI:
  - a) Shree Vardayini Chemicals Industries Pvt. Ltd.
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all the interested parties to the extent considered relevant have been taken into account in this final finding.

- xii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiii. Further information was sought from the applicant and the other interested parties to the extent deemed necessary.
- xiv. Verification of the domestic industry and the supporter was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- xv. Investigation was carried out for the period starting from April 2021 to 31st March 2022 (12 months) (hereinafter referred to as the “period of investigation” or the “POI”). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from April 2018 – March 2019, April 2019 March 2020, April 2020 - March 2021 and the POI
- xvi. Request was made to the DG Systems to provide the details of imports of the subject goods during the last four years, including the period of investigation, and the same was received by the Authority. The Authority has used the DG system import data for computation of the volume and value of imports and injury analysis.
- xvii. In accordance with Rule 18 of the Anti-Subsidy Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in hearing held on 23<sup>rd</sup> May, 2022. All the parties were requested to submit their written submissions latest by 30<sup>th</sup> May, 2021. Since there was no opposition, there was no rejoinder submissions due.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.
- xix. \*\*\* in this final finding represents the information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1 USD=Rs. 75.14

## **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION/ PRODUCT UNDER INVESTIGATION AND LIKE ARTICLE**

### **A.1 Product Under Consideration (PUC) and Product Under Investigation (PUI)**

#### ***C.1 Views of the domestic industry***

7. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and the like article:
  - i. The product involved in the previous investigations and the present investigation is “*Saccharin in all its forms*”.
  - ii. *Saccharin is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheadings No. 29251100. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.*
  - iii. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported into India. They are comparable in terms of the technical specifications, quality, functions or end-uses. The two are technically and commercially substitutable. Hence, should be treated as like articles in accordance with the Rules.

#### ***C.2 Views of the other interested parties***

8. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles.



### C.5 Examination by the Authority

9. The present investigation is an anti-circumvention investigation of duties imposed on the imports of “Saccharin” originating in or exported from China PR. Therefore, the scope of the product under consideration in the present investigation, remains the same as defined in the original Countervailing Duty/ Anti-subsidy investigation, i.e. final findings dated 19.06.2019, which is reproduced herein below:

*“The product under consideration in the present investigation is “Saccharin in all its forms”. “Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble saccharin is called saccharin or saccharin acid. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation.”*

10. The product under consideration (PUC) is “Saccharin” originating in or exported from China PR. The product under investigation (PUI) is “Saccharin” exported from Thailand also referred to as “Product under Investigation” or “PUI” classified under subheadings No. 29251100 of the Customs Tariff Act.
11. The Authority notes from the information on record that the subject goods produced by the domestic industry is “like article” to the goods imported from Thailand. The subject goods produced by the Indian industry and imported from Thailand are comparable in terms of technical specifications, functions or end-uses product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
12. The above-stated classification of the product under investigation considered, however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

## D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

### D.1 Views of the Domestic Industry

13. The domestic industry has made following submissions with regard to the domestic industry and standing:
  - i. M/s. Swati Petro Products Private Limited has filed the application for anti-circumvention investigation. The product under consideration is produced by four producers in India. The application has been supported by M/s. A. S. Chemopharma Pvt. Ltd., and M/s. Shree Vardayini Chemicals Industries Pvt. Ltd.
  - ii. The applicant satisfies the standing requirement and constitutes domestic industry within the meaning of the AD Rules.

### D.2 Views of the other interested parties

14. None of the exporters, importers, consumers and any other interested parties has filed any comment or submission with regard to standing of the domestic industry.

### D.3 Examination by the Authority

15. The application has been filed by M/s Swati Petro Products Private Limited. The application has been supported by M/s. A. S. Chemopharma Pvt. Ltd., and M/s. Shree Vardayini Chemicals Industries Pvt. Ltd. Shree Vardayini Chemicals Industries Pvt. Ltd. M/s Shree Vardayini Chemicals Industries Pvt. Ltd. have also filed information on capacity, production and sales.
16. Information on record shows that the production by the applicant constitute 30% of the total Indian production. The applicant, thus, constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b).

**E. EVIDENCE OF CIRCUMVENTION****E.1 Views of the domestic industry**

17. The following submissions were made by the domestic industry:

- i. The exports from Thailand are not of “saccharin” produced in Thailand. Rather, these products are of Chinese origin which are merely being exported through Thailand, to avoid payment of countervailing duties.
- ii. The subject goods were earlier shipped directly to India from China PR. However, due to the imposition of countervailing duties on imports of saccharin from China PR, the import volumes have declined from China PR and those from Thailand have started in significant volume.
- iii. The exports from China to Thailand have increased significantly in the POI thus showing dependency of that country on imports, rather than manufacturing. Since the imports from Indonesia also declined post imposition of antidumping duty, the exports from Indonesia to Thailand was also analysed. There are no exports of Saccharin from Indonesia to Thailand. These facts clearly show that the Chinese goods that are being circumvented through Thailand.
- iv. None of the exporters have responded to the investigation and thus there is no information or claim of genuine production in Thailand.
- v. Volume of imports into India from China PR has declined since the imposition of countervailing duty on imports of the product under consideration. However, imports from Thailand started and has now intensified.
- vi. Post imposition of duties, the imports from China PR and Indonesia declined significantly. However, the market share vacated by the imports from China PR and Indonesia has been taken away by the imports from Chinese exporters through Thailand. Thus, the domestic industry has been deprived of the legitimate fair share of the market.
- vii. Almost 10% of the domestic market is captured by Thailand. The market share of Chinese originated goods has reached 31% in the POI (along with circumvented imports from Thailand) and the market share of Indian industry as a whole has reduced to 62% in the POI
- viii. The landed price of the imports consigned from Thailand are significantly below the selling price in India, thus significantly undercutting the prices in the domestic market. Price undercutting has increased significantly in the POI, when compared to the previous years
- ix. China’s circumvention has resulted in (a) loss of Indian industry’s market share in demand; (b) significant price undercutting; and (c) Erosion of Duty.
- x. Significant imports consigned from Thailand were cleared by the customs after payment of full customs duty. Under the ASEAN–India Free Trade Area (AIFTA), the product under consideration is exempted from payment of basic custom duties. There is no reason why a genuine producer should export the product with imports attracting full custom duties, when they can easily avail concessional benefits under AIFTA
- xi. The European Commission in numerous decisions have concluded circumvention based on change in trade pattern and undermining the remedial effect on the basis of import statistics solely. The presence of production facility in the country concerned is not even a question for determination.

**E.2 Views of the other interested parties**

18. The following submissions were made by the other interested parties:

- i. The regional content value should be checked in imports from Thailand & Cambodia. It should be minimum 35%. Carotar declaration should be scrutinized. Asean-India Free Trade Agreement (AIFTA) Certificate Of Origin should be scrutinized.
- ii. Imports from Thailand & Cambodia primarily looks suspicious. There are strong chances of evasion of duty / misdeclaration which needs to be ascertained. The exporter is from a different country. The financial transactions need to be checked.

- iii. Scrutinize the documents from the exporters & importers involved. Their names are not mentioned in the NCV of domestic industry.
- iv. There is no basic duty & cess on basic duty & no GST on basic duty & no GST on cess on imports from Thailand & Cambodia.
- v. Physical verification of exporter should be done.
- vi. Thailand & Cambodia can buy from any country. So, China should not be cornered.
- vii. Landing cost from China is very high.
- viii. The dumping from Thailand & Cambodia are spoiling the prices locally as China is not competitive.

### E.3 Examination by the Authority

19. The Authority notes that the submissions made by various interested parties and the relevant provision of the Act/Rules as under:

*Rule 25 of CVD Rules:*

*Circumvention of countervailing duties. — (1) Circumvention shall be considered as a change in the pattern of trade between any country and India or between individual companies in any other country, subject to measures and India, as a result of a practice, process or work for which there is insufficient cause or economic justification other than the imposition of the duty, and where there is evidence of injury or that the remedial effects of the duty are being undermined in terms of the prices or quantities or both of the like product, and that the imported like product or parts thereof or both still benefit from the subsidy as determined in original or previous determination.*

*(2) The practice, process or work referred to in the sub-rule (1) includes, inter alia,-*

*(a) where an article subject to countervailing duty is imported into India from any country including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of countervailing duty, in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India or in any other country, such assembly, finishing or completion shall be considered to circumvent the countervailing in force if,-*

*(i) the operation started or increased after, or just prior to, the countervailing investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of countervailing duty; and*

*(ii) the value consequent to assembly, finishing or completion operation is less than thirty-five percent of the cost of assembled, finished or complete article.*

*Explanation I. 'Value' means the cost of assembled, complete or finished article less value of imported parts or components.*

*Explanation II. - For the purposes of calculating the 'value', expenses on account of payments relating to intellectual property rights, royalty, technical know-how fees and consultancy charges, shall not be taken into account.*

*(b) where an article subject to countervailing duty is imported into India from country of origin or country of export notified for the levy of countervailing duty after being subjected to any process involving alteration of the description, name or composition of an article, such alteration shall be considered to circumvent the countervailing duty in force if the alteration of the description or name or composition of the article subject to countervailing duty results in the article being altered in form or appearance even in minor forms regardless of the variation of tariff classification, if any;*

*(c) where an article subject to countervailing duty is imported into India through any exporter or producer or country not subject to countervailing duty, such exports shall be considered to circumvent the countervailing duty in force if the exporters or producers notified for the levy of countervailing duty change their trade practice, pattern of trade or channels of sales of the article in order to have their products exported to India through any exporter or producer or country not subject to countervailing duty;*

*(d) any other manner where the countervailing duty so imposed is rendered ineffective.*

20. For the purpose of examination of imports of both the PUC and the PUI, the petitioner provided transaction wise import data from Trade Map in view of non availability of the same by DGCI&S. The Authority, however, has considered transaction wise data provided by the DG systems for analysing the import of the PUI and the PUC in India. For the purpose of analysis of export by Thailand to third countries and import in Thailand by other countries, Trade Map data has been considered.
21. The Authority notes that the CVD measure is producer/exporter specific. The producers/exporters subjected to a CVD investigation need to provide relevant data/ information so that the Authority can make a determination. The Authority notes that none of the producer/exporters of PUI have provided any information.

### **E.3.1 Change in the pattern of trade**

22. The Authority has examined the stipulated criteria on shift in trade pattern to PUI from PUC i.e. whether the change in trade pattern is stemmed from an economic justification or is on account of levy of CVD on the PUC, in accordance with Rule 25(1).
23. The change in pattern of trade has been analysed from 2018-19 to the POI, analysing the volume of imports of the PUC and PUI.

<b>Years</b>	<b>Imports of PUI (MT)</b>	<b>Imports of PUC (MT)</b>
2018-19	-	712
2019-20	-	776
2020-21	23	776
2021-22	176	455

Source: DG SYSTEMS

24. It is seen that the imports from Thailand that were otherwise non-existent till 2018-19, started entering the domestic market for the first time in 2020-21. Correspondingly, after the imposition of countervailing duties on China on 30<sup>th</sup> August, 2019, the volume of imports from China started declining.
25. The Authority has also examined imports of Saccharin into Thailand from various countries globally, and exports of Saccharin from Thailand to other countries.

<b>Particulars</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Imports into Thailand (MT)	1,054	1,008	1,044	1,432	1,584
Import price (USD/kg)	7.45	7.95	11.55	7.18	7.13
Exports from Thailand (MT)	0.36	0.78	6.80	157	1,185
Export price (USD/kg)	25.21	23.23	1.76	5.75	6.44

Source: Trade Map

26. The following is observed:
- Thailand has been historically importing saccharin. These imports increased from 1044 MT 2019 to 1432 MT in 2020 and 1584 MT in 2021. There were, however, nil or low exports from Thailand till 2019.
  - Majority of the imports in Thailand (about 95% over the period 2017 to 2021) are from China, while some volumes have been imported from other countries as well, including India, Japan and South Korea.
  - Export price from Thailand to India and other countries is lower than import price into Thailand.
27. The Authority also notes that exporters from Thailand have preferred not to cooperate and have not provided any information whatsoever with regard to the origin of the material exported to India which indicates that there are no genuine producers in Thailand.

28. Further, the domestic industry has provided evidence showing exporters in Thailand are routing the PUI produced in China. Since there is no other evidence given by any party to show domestic production of the product in Thailand, and neither that any of the producers/exporters have cooperated, the Authority holds that the goods exported from Thailand are of Chinese origin which incorporated the subsidy provided by China PR in this product which has already been quantified in the original investigation.

### **E.3.2 Justification Economic or otherwise other than imposition of anti-subsidy duty**

29. It is noted that the imports from Thailand are attracting concessional customs duty under the ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA). The present basic customs duty on import of Saccharin is 10% whereas the preferential tariff for import of sachharin from Thailand is 0% under AIFTA. As per the information available in transaction wise import data of DG Systems, it is noted that all imports from Thailand during 2020-21 and the POI have been made after payment of full customs duty whereas all imports from China PR during the same period have been made after payment of customs duty and countervailing duty, as applicable.
30. It is also noted that whereas the applicant has claimed that there is no producer of Sachharin in Thailand, the transaction wise import data indicates that imports from Thailand in India are of Thailand origin. In this regard, the Authority notes that the applicant has submitted evidence indicating that the PUI imported from Thailand are in fact of Chinese origin.
31. Further, in the absence of any cooperation from producer/exporter from Thailand, it appears that while the exporters have undertaken some insignificant activity leading to the change in country of origin, but the same is not enough to avail concessions under either AIFTA, nor sufficient to establish that the exports do not constitute circumvention of duty.
32. The Authority, therefore, holds that imports from Thailand are infact of Chinese origin and there is no other due cause or economic justification for the transshipment of PUC from PUI other than the avoidance of the payment of the countervailing duty in force on import of Sachharin originating in or exported from China PR.

### **E.3.3 Assessment of effect of circumvention on existing Anti-subsidy measures and the domestic industry.**

33. An essential aspect in an anti-circumvention investigation whether remedial effects of the anti-subsidy duty imposed earlier are being undermined. The Authority therefore examined the manner in which and to the extent the circumvented products are undermining the duty imposed and thereby rendering such duty as redundant. The Authority has examined whether the remedial effects of anti-subsidy duties are undermined in terms of market share and price undercutting due to imports of the product under investigation from Thailand.

#### **F.3.3.1 Market share assessment**

34. The Authority has examined market share of imports of the PUI in the demand of the subject goods in India as provided under:

<b>Market Share in Demand</b>	<b>Unit</b>	<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>	<b>POI</b>
Sales of Indian industry	%	42	50	55	62
Subject Country - Thailand	%	0	0	1	10
Country attracting CVD-China	%	36	45	39	21
Other Countries	%	22	5	5	7
Total Demand Share	%	100	100	100	100

35. It is seen that there were no imports from Thailand in the domestic market until 2019-20. However with duties imposed on China PR, Thailand captured one percent market in 2020-21 and its share increased to 10% in the POI. Market share of China PR decreased from 39% in 2019-20 to 21% in the POI. The domestic industry had been able to increase some market share post imposition of countervailing duties on China, however, it has been prevented from further increasing its legitimate market share because of Chinese subsidised exports being circumvented through Thailand.

### F.3.3.2 Effect of circumvention on Net Sales Realization of PUC of the domestic industry during the POI

36. With regard to the effect of imports of the PUI on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the circumvented imports as compared to the price of the like products in India. The Authority has considered the same as under:

Price Undercutting	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Landed price of imports from Thailand	Rs/kg	-	-	474	532
Net sales realization	Rs/kg	-	-	***	***
Net sales realization	Trend			100	103
Price undercutting	Rs/kg	-	-	***	***
Price undercutting	Trend			100	71
Price undercutting	%	-	-	***	***
Price undercutting	% Range	-	-	20-30	10-20

37. It is seen that the landed price of imports from Thailand is below the selling price of the domestic industry since the time it started entering the domestic market in 2018-19.

38. The Authority has examined the undercutting level from China in the table below:

Price Undercutting	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Landed price of imports from China PR	Rs/kg	450	473	668	602
Landed with CVD	Rs/kg	450	473	791	713
Net sales realization	Rs/kg	***	***	***	***
Net sales realization	Trend	100	112	121	126
Price undercutting (without CVD)	Rs/kg	***	***	***	***
Price undercutting (without CVD)	Trend	100	176	-143	46
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	0-10	10-20	Negative	0-10
Price undercutting (with CVD)	Rs/kg	***	***	***	***
Price undercutting (with CVD)	Trend	100	176	-411	-196
Price undercutting (with CVD)	%	***	***	***	***
Price undercutting (with CVD)	% Range	0-10	10-20	Negative	Negative

39. The anti-subsidy duties were imposed in August 2019. Thus, the duties were effective in the POI. It is seen that price undercutting on imports of PUC from China PR (with CVD) was negative during the POI.

### F.3.3.3 Countervailing benefits are applicable on goods being exported from Thailand

40. Examination of evidence on record evidences that the goods being exported through Thailand are the goods originating in China PR. On account of the fact that none of the producers/exporters from Thailand have participated in the investigation to evidence that the PUI imported in India were produced in Thailand, the Authority holds that the PUI imported in India is of Chinese origin and have thus benefited from the subsidies that were earlier found to have benefited the Chinese manufacturers. This is particularly so when the nature of subsidies earlier determined to have benefited the exports were either linked to the production or exports as such, and were not limited only on direct exports to India only.

**F.3.3.4 Erosion of efficacy of existing countervailing duty on PUC during the POI**

41. The Authority has determined the quantum of ADD that would have been payable on imports of the product under investigation from Thailand. The Table below quantifies the the amount of erosion of anti-dsubsidy measures on PUC:

Period	Imports-Quantity from Thailand	CIF price	Anti-Subsidy Duty on PUC - China	Anti-Subsidy Duty	Quantum of erosion of Countervailing Duty
	MT	Rs./kg	%	Rs/kg	Rs.Lacs
2018-19	-		20		
2019-20	0		20		
2020-21	23	474	20	94.6	22
2021-22	176	532	20	106.4	187
<b>Total</b>					<b>209</b>

42. It is seen that an amount of Rs.209 lacs was payable on these imports as countervailing duty, if these were declared as of Chinese origin.

**G. POST DISCLOSURE COMMENTS****G.1 Comments made by the domestic industry**

43. The domestic industry has agreed with the observations of the Authority. It is reiterated that:

- Volume of imports into India from China has declined since imposition of countervailing duty on imports of the product under consideration. Correspondingly, imports from Thailand started and has now intensified. Thus there is clear change in the pattern of trade.
- There have been no imports from Thailand earlier and there is no known producer involved in the manufacturing, there can be no other justification, economic or otherwise, apart from imposition of countervailing duty on China PR, for the above change in pattern of trade, as the import price from Thailand is much below the level of import price from China even without adding countervailing duty. The only objective appears to be circumvention of the countervailing duty in place.
- The landed price of imports consigned from Thailand are significantly below the selling price in India, thus significantly undercutting the prices in the domestic market.
- The market share of Thailand has increased. The domestic industry had been able to increase some market share post imposition of countervailing duties on China, however, it has been prevented from further increasing its legitimate market share because of Chinese subsidised exports being circumvented through Thailand.
- The Authority has noted that all imports from Thailand during 2020-21 and the POI have been made after payment of full customs duty. Thus despite having a concessional duty under FTA, the exporters are not able to utilize the duty exemption given because the exporters have not been able to fulfil the rules of origin requirements under the FTA. This strengthens the argument that the goods are of Chinese origin.
- The PUI imported in India is of Chinese origin and have thus benefited from the subsidies that were earlier found to have benefited the Chinese manufacturers. There is no evidence to show that the benefits that were available to the producers in China have ceased to exist.

**G.2 Submissions made by other interested parties**

44. None of the exporters, importers, consumers, and other interested parties has filed any comment or submissions, post issuance of the disclosure statement.

**G.3 Examination by the Authority**

45. The Authority notes that most of the submission by the domestic industry and interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in this finding.



**H. CONCLUSIONS**

46. Having examined the contentions of the domestic industry and other interested parties and based on the analysis as above, the Authority concludes that:
- i. The Authority notes that there has been a change in pattern of trade in case of the PUI. It is seen that the imports from Thailand that were otherwise non-existent till 2018-19, started entering the domestic market for the first time in 2020-21. Correspondingly, after the imposition of countervailing duties on China on 30th August, 2019, the volume of imports from China started declining.
  - ii. The goods exported from Thailand are of Chinese origin which incorporated the subsidy provided by China PR in this product which has already been quantified in the original investigation.
  - iii. There is no other due cause or economic justification for the transshipment of the PUC from the PUI other than the avoidance of the payment of the countervailing duty in force on import of Sachharin originating in or exported from China PR.
  - iv. Imports of PUI from Thailand are entering at dumped prices.
  - v. The import of PUI have undermined the remedial effect of existing CVD measure on the PUC imposed vide Custom Notification No. 02/2019 -Cus(CVD) dated 30<sup>th</sup> August, 2019.
  - vi. The commercial gain due to evasion of countervailing duty on the PUC has benefitted the producers/exporters by exporting the PUI through Thailand.
  - vii. The Authority has also received comments on the investigation from an importer, M/s Sandeep Organics Private Limited. The said importer has stated that the imports from Thailand and Cambodia primarily look suspicious and there are strong chances of evasion of duty / misdeclaration which needs to be ascertained as the the exporter is from a different country. The Authority, noting, the contentions of the importer has considered the same while examining the various aspects of the circumvention phenomena.

**I. RECOMMENDATION**

47. The Authority keeping in view the aforesaid, recommends extension of the existing countervailing duty on the subject goods originating in or exported from China PR, imposed vide Custom Notification No. 02/2019-Cus (CVD) dated 30<sup>th</sup> August, 2019, on the import of Saccharin originating in or exported from Thailand.
48. The validity of the countervailing duty on the imports of Saccharin originating in or exported from Thailand would be co-terminus with the countervailing duty on the import of Saccharin originating in or exported from China PR, imposed through Custom Notification No. 02/2019-Cus (CVD) dated 30<sup>th</sup> August, 2019.

**J. FURTHER PROCEDURE**

49. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority